

उत्तराखण्ड शासन
राजस्व अनुभाग-3
संख्या: 205 /XVIII(3)/2017-02(21)2016-TC
देहरादून: दिनांक: 23, मई, 2017

अधिसूचना

चूंकि समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के भूमि अधिग्रहण के कारण व्यक्तियों को गैर-स्वैच्छिक विस्थापन होने की सम्भावना है, ऐसी स्थिति में यथास्थिति पुनर्वासन अथवा पुनर्व्यवस्थापन के लिए;

राज्यपाल, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2013) की धारा 43 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जनपद चमोली के अपर जिलाधिकारी को उनके पद के अतिरिक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त करने तथा उक्त धारा की उप धारा (2) में अवसंरचना आदि उपलब्ध कराये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल उपधारा (3) के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि एतद्वारा नियुक्त पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक राज्य सरकार और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन रहते हुए पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम की विरचना, निष्पादन और अनुश्रवण प्रशासक में निहित होगी।

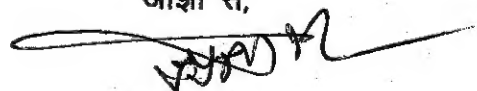
हरबंस सिंह चुघ
प्रभारी सचिव।

संख्या-205/XVIII(3)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
4. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, देहरादून।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।
8. मुख्य परियोजना प्रबन्धक, रेल विकास निगम लि०, ऋषिकेश।
9. जिलाधिकारी, चमोली।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को मुद्रित कराकर 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. प्रभारी अधिकारी, एन०आई०सी०, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून को इन्टरनेट पर प्रसारण हेतु।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 205 dated 23rd May for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
RAJASWA ANUBHAG
No. 205/XVIII(III)/2017-02(21)/2016-TC
DEHRADUN: DATED: 23, May, 2017


NOTIFICATION

Whereas the State Government is satisfied that there is likely to be non-voluntary displacement of persons due to acquisition of land for Rishikesh-Karnprayag New Broad Gauge Rail Line Project rehabilitation and resettlement as the case may be,

Now, therefore in exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 43 of the Right to Fair Compensation and transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act No.30 of 2013), the Governor is pleased to **appoint as a rehabilitation and resettlement administrator addition in his duties to the additional district magistrate of District Chamoli** and to provide office infrastructure etc. in the said sub-section (2).

2- The Governor is also pleased to direct under sub-section (3) that the hereby appointed administrator State Government for rehabilitation and resettlement with subject to the superintendence, directions and control of the Commissioner for rehabilitation and resettlement and the formulation, execution and monitoring of the rehabilitation and resettlement scheme shall be vest in the administrator.

By order,


(Harbans Singh Chugh)
Secretary In-charge